>

Title: Need to provide result based grant to schools and include unaided schools under Secondary Education Yojana.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अति लोक महत्व के विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना है, इसमें 75 प्रतिशत केन्द्र का अंश है और 25 प्रतिशत राज्य का अंश है। मानदेय के संबंध में उत्तर प्रदेश में कुल वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या 12607 है। वित्तविहीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत 2011 में वर्तमान परीक्षा में 71 परसेंट है। कार्यरत कर्मचारी 1,30,700 से अधिक हैं। राजकीय विद्यालयों की संख्या 570 है और सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 5558 है। अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत इस विद्यालय में 29 प्रतिशत है। जिन राज्यों में योजना लागू नहीं है, उनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण जगह यह लागू है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर रिज़ल्ट आधारित अनुदान दिया जाए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वित्तविहीन विद्यालयों को सम्मिलित किया जाए। उदाहरणस्वरूप गुजरात और राजस्थान में वित्तविहीन विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है और बिहार सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों को रिज़ल्ट आधारित अनुदान दिया है। उसी के अनुसार इसको उत्तर प्रदेश में भी लागू करें।